भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2403**
दिनांक 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन,1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत निजी कंपनियों को विमानपत्तन

2403. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई तुल्नात्मक अध्ययन किया गया है कि दीर्घावधि में देश के विमानन क्षेत्र के विकास के लिए विमानपत्तनों का सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अनुरूप निर्माण और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारिता वास्वतम में लाभप्रद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का पीपीपी मॉडल के अंतर्गत अनेक विमानपत्तनों के नियंत्रण को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में वर्तमान में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित प्रत्येक विमानत्तन द्वारा अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) एक सफलता की कहानी रही है। हवाईअड्डों पर पीपीपी से विश्वस्तरीय हवाईअड्डों के सृजन में और हवाईअड्डों पर यात्रियों तक कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने में मदद मिली है, जो इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि मौजूदा पीपीपी हवाईअड्डे, यथा दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर और हैदराबाद

निरंतर एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल और स्काईट्रैक्स रिसर्च एवार्डस द्वारा प्रकाशित हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) रेटिंग में अपनी अपनी श्रेणियों में दुनिया के शीर्ष पांच हवाईअड्डों में शामिल होते रहे हैं। पीपीपी हवाईअड्डों पर सृजित विश्वस्तरीय अवसंरचना के परिणामस्वरूप एयरलाइनों के स्लॉट्स में वृद्धि हुई है और उनकी सेवाओं के कुशल प्रबंधन में सुधार हुआ है। हवाईअड्डों पर पीपीपी से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को अपने राजस्वों में इजाफा करने और दूसरी तथा तीसरी श्रेणी (टींयर-।। और टीयर-।।।) के शहरों में हवाईअड्डों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त, एएआई हवाईअड्डों पर हवाई दिक्चालन सेवाएं मुहैया कराने के अपने सांविधिक कार्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने में भी समर्थ रहा है, जिसके फलस्वरूप सिविल प्रचालनों में कुशलता में वृद्धि हुई है।

(घ): पिछले पांच वर्ष के दौरान मुम्बई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरू हवाईअड्डों पर अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 17.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2403 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

मुम्बई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु हवाईअड्डों पर अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा

हवाईअड्डे का नाम	अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में)				
	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई	2772.54	3150.27	3545.22	3847.44	3552.70
कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा	530.78	487.27	553.41	650.34	655.04
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली	5015.98	5719.29	3836.93	3714.56	3707.77
राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद	645.60	1195.90	1331.50	1549.80	1623.30
कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु	1127.73	1314.35	1498.97	1417.35	1343.00